भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)
11, अशोक रोड नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23005700 ; **फैक्स** : 23005787

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की स्थिति के बारे में मंगलवार, 16 सितम्बर, 2008 को जारी प्रेस वक्तव्य

सीरियल धमाके देश को काफी समय से दहलाते जा रहे हैं। अब बेगुनाह लोगों की निर्मम मौत का सिलसिला संप्रग सरकार की नाक के ठीक नीचे राजधानी तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी का गृहमंत्री द्वारा अपनी नई–नई पोशाक पहनने से कोई वास्ता नहीं है, किंतु पार्टी यह अवश्य जानना चाहेगी कि इस आए दिन हो रही विनाशलीला और खून–खराबे के लिए कौन जवाबदेह है। प्रधानमंत्री को साफ तौर पर बताना होगा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जोकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेवार और सरकार के प्रति जवाबदेह है, आतंकवाद पर काबू पाने के लिए कड़ा कानून बनाने की वकालत कर रहे हैं या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की इस सलाह की जानकारी सारी जनता तथा पूरे राष्ट्र को दी जानी चाहिए कि क्या देश को आतंकवाद के बारे में कठोर कानून की जरूरत है या नहीं। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आतंक पर पोटा जैसे कठोर कानून को बनाए जाने का जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है, जिसको गृहमंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की सरकारों द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध बनाए गए कानून का भी समर्थन किया था। यदि संप्रग सरकार के पास आतंकवाद से लड़ने के लिए कोई नुस्खा नहीं है तो उसे यह बात क्यों नहीं स्वीकार कर लेनी चाहिए और संप्रग सरकार द्वारा शुरू किए गए और अमल में लाए गए कठोर फार्मूलों का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए, जिनमें पोटा भी शामिल है।

ऐसी रिपोर्ट मिली है कि संप्रग की मुखिया के अधीन जो बैठक हुई थी तथा जिसमें मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने गृहमंत्री पर "इंटेलीजेंस विफलता" का आरोप लगाया था, उसमें गृहमंत्री की तीखी आलोचना हुई थी। प्रधानमंत्री को बिना लाग–लपेट उत्तर देना चाहिए कि इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है – विशेषकर तब जबकि गृहमंत्री का यह दावा है कि सरकार को दिल्ली पर संभावित आतंकी हमले की जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सूचित किए जाने से पहले ही थी। देश की आरोप–प्रत्यारोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जोकि पहले ही बहुत हो चुका है। ऐसा करके सरकार ने आतंकी मोर्चे पर अपनी विफलता स्वीकार कर ली है। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे वर्तमान गृहमंत्री को आगे भी सरकार में बनाए रखना चाहते हैं। रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को जो अपना भाव ऊंचा रखने के लिए "इंटेलीजेंस विफलता" की धूल उड़ा रहे हैं को पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जब उन्होंने सिमी पर से प्रतिबंध हटाए जाने का स्वागत किया था – उस सिमी पर से जिस पर अपने लड़ाकू संगठन "इंडियन मुजाहिद्दीन" के माध्यम से हाल के धमाके किए जाने का आरोप लगा है।

गृहमंत्री के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के नाजुक मसले को संभालने का कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं है, क्योंकि वे कुर्सी के प्रति वफादार हैं। क्या इसीलिए वे आंतरिक सुरक्षा विभाग को संभालने के लिए योग्य हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गृहमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा स्वयं राष्ट्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि वे प्रत्यक्षतः कांग्रेस हाई कमांन के प्रति अधिक प्रतिबद्ध लगते हैं, जैसाकि उनकी हाल की सार्वजनिक टिप्पणियों से स्पष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि गृहमंत्री की प्राथमिकता क्या है – देश की सुरक्षा या श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति वफादारी ?

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी